## अंदर के पन्नों पर


- दो बार भेजा गया था सीवीओ के लिए संजीव का नाम >> 5
- तापमान 40 पर पहुंचा, बारिश के आसार नहीं >> 6
- फिरौती नहीं देने पर व्यवसायी की हत्या >> 7


## जागरण सिटी


- शुरू हुआ पुस्तक मेला >> I
- भक्तों के बीच 'फ्रेंडली' हो रहे इको फ्रेंडली गणेश >> I
- चोरों और लुटेरों से अब खुद निपटेंगे लोग >> I
- मेट्रो एलाइनमेंट में होगा बदलाव >> I


## एक नजर

### डीयू कोर्ट में चुने गए कार्यकारी परिषद के सदस्य

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :** दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में कार्यकारी परिषद की सदस्यों का चुनाव शुक्रवार की देर रात संपन्न हो गया। डीयू कोर्ट के चुनाव परिणाम देखने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल तीन राजनीतिक खेमें में बंटे डीयू में कांग्रेस समर्थित सदस्यों का चुनाव अधिक हुआ है। हालांकि, कार्यकारी समिति में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के राजेश गोगना, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के अजय कुमार, एकेडमिक फार एक्शन एंड डेवलेपमेंट जेएल गुप्ता तथा इंटेक के अनुराग कुमार चुने गए हैं। कोर्ट के चुनाव में भी अधिकांश लोग कांग्रेस समर्थित हैं।

### आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म

**जासं, पूर्वी दिल्ली :** पूर्वी जिले के न्यू अशोक नगर इलाके में आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा है। जान से मारने की धमकी देकर उसने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया। पुष्टि के बाद मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

# 12 साल में 20 लाख फ्लैट की योजना

## तीन महीने में मूर्त रूप लेगी लैंड पुलिंग योजना, राजधानी में निजी कंपनियां उपलब्ध कराएंगी आवास

**वीके शुक्ला, नई दिल्ली**

**ग्रेटर नोएडा**, इंदिरापुरम, फरीदाबाद व गुड़गांव की मल्टीस्टोरी इमारतों का लुक शीघ्र ही राजधानी में भी दिखाई देगा। डीडीए के अधिकारियों की मानें तो भवन निर्माण के क्षेत्र की एनसीआर की दो दर्जन से अधिक कंपनियां दिल्ली की ओर रुख करने के मूड में हैं। क्योंकि दिल्ली में महत्वाकांक्षी लैंड पूलिंग योजना तीन महीने में मूर्त रूप ले लेगी। पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली में आगामी 10 से 12 साल में 20 लाख आवास उपलब्ध कराने की डीडीए की योजना है। इसके लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया जा चुका है।

डीडीए उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार का कहना है कि आगामी तीन माह में पॉलिसी को हर हाल में जमीन पर उतार दिया जाएगा। पॉलिसी के बाद दिल्ली में निजी कंपनियों द्वारा आवास उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी तक दिल्ली में निजी कंपनियों को आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति नहीं है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद निजी कंपनियां सीधे किसानों से जमीन खरीद सकेंगी और जमीन पर फ्लैट बना सकेंगी। जिससे किसानों को जमीन का अधिक पैसा मिल सकेगा। बिल्डरों के माध्यम से आवास शीघ्र बन सकेंगे।

डीडीए इन्हीं फ्लैटों के आवंटन के लिए ला रहा है योजना।

### दो कंसल्टेंट नियुक्त करने की योजना

इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए डीडीए की दो अलग-अलग कंसल्टेंट नियुक्त करने की योजना है। ये कंसल्टेंट वहां वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं जुटाने में मदद करेंगे। दिल्ली 20 से 24 हजार हेक्टेयर जमीन ऐसी है, जो लैंड पूलिंग योजना में शामिल हो सकेगी।

- एनसीआर की दो दर्जन से अधिक कंपनियां करेंगी दिल्ली का रुख
- निजी कंपनियां सीधे किसानों से खरीद सकेंगी जमीन

### क्या करेंगे कंसल्टेंट

लैंड पूलिंग योजना में विस्तार की सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है। इसके लिए दो अलग-अलग कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। एक कंसल्टेंट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए काम करेगा। जबकि दूसरा कंसल्टेंट लोगों की जरूरत के मुताबिक परिवहन व सड़कों का खाका तैयार करेगा। डीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार लैंड पूलिंग की जमीन को डीडीए किसानों से अपने कब्जे में लेगा। उस जमीन का आन्तरिक विकास कर एक बड़ा हिस्सा का वापस कर देगा। किसान व बिल्डर इस जमीन पर फ्लैट बनाकर बिक्री कर सकेंगे। बाकी जमीन पर डीडीए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।

## क्या है लैंड पुलिंग पॉलिसी

**श्रेणी नंबर एक**

इसमें 2 से 20 हेक्टेयर जमीन वाले किसान/बिल्डर शामिल होंगे। इन किसानों की 60 फीसद जमीन डीडीए सड़क, बिजली व पानी तथा सीवर लाइन व अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए लेगा तथा 60 फीसद जमीन किसानों को वापस कर देगा। इस 60 फीसद जमीन पर बिल्डर फ्लैट बनाएंगे।

**श्रेणी नंबर दो**

यह श्रेणी 20 हेक्टेयर से बड़े किसानों की होगी। इस श्रेणी में 60 फीसद जमीन किसान/बिल्डर को मिलेगी तथा 40 फीसद जमीन डीडीए के पास रहेगी।

- दोनों श्रेणियों में जो जमीन किसानों को बिल्डरों को मिलेगी, उस जमीन का 53 फीसद हिस्सा आवासीय, 5 फीसद व्यावसायिक व 2 फीसद कम्युनिटी सर्विस के लिए आरक्षित होगा। किसानों/बिल्डरों को 15 फीसद ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाना अनिवार्य होगा।
- इस पॉलिसी के बाद किसानों को अपनी जमीन की कीमत भी पहले की अपेक्षा अधिक मिल सकेगी। क्योंकि किसानों की जमीन खरीदने के लिए बिल्डरों में प्रतिस्पर्धा होगी। जिससे किसान को लाभ होगा। आवासीय परिसर विकसित करने तक बिल्डर को किसानों को साथ रखना होगा। क्योंकि जमीन के मामले में डीडीए में सभी कागजी कार्रवाई किसानों की ओर से ही होगी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए द्वारका सेक्टर-23 में डीडीए द्वारा बनाए गए फ्लैट।

# सिर्फ चार तारीखों के बीच बना चार मंजिला मकान

**पवन कुमार, नई दिल्ली**

अवैध निर्माण के प्रति दिल्ली पुलिस और नगर निगम इस कदर सुस्त हैं कि वे न तो खुद कार्रवाई करते हैं और न ही अदालत के आदेश पर कार्रवाई की जाती है। जिसके कारण अवैध निर्माण तेजी से फल-फूल रहा है। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस और नगर निगम पैसे लेकर अवैध निर्माण कराते हैं। यही कारण है कि एक मकान की नींव की खोदाई के समय दी गई शिकायत पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए थे और चार मंजिला मकान भी बन गया, मगर कार्रवाई नहीं की गई। यह मामला पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। यह टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने अवैध निर्माण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की है।

खंडपीठ ने बाटला हाउस में एक जगह पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने पुलिस से कहा है कि वह अवैध निर्माण कर बनाई गई इमारत को सील करे और अपनी रिपोर्ट अदालत को दे। वहीं, अदालत ने मामले में संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश डीसीपी को जारी किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

खंडपीठ ने कहा कि उन्हें हैरत है कि उन्होंने मामले में अवैध निर्माण रोकने के आदेश दिए थे। मगर, पुलिस ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। उनके आदेश के बाद केस में अभी तक चार तारीख पड़ चुकी हैं और हर तारीख पर याचिकाकर्ता ने एक नया फ्लोर बनाए जाने संबंधी सुबूत और फोटो पेश किए। ताज्जुब की बात है कि नगर निगम की ओर से मांग के बाद भी उन्हें कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता नहीं दी गई। पुलिस का यह रवैया यह संदेह पैदा करता है कि पुलिस खुद पैसे लेकर अवैध निर्माण करा रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता शोएब हैदर ने अदालत को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। वे आगामी दो दिन के भीतर कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश कर देंगे।

- लगता है दिल्ली पुलिस पैसा लेकर खुद अवैध निर्माण कराती है: हाईकोर्ट

- अदालत ने अवैध निर्माण को लेकर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

### यह है पूरा मामला

बाटला हाउस निवासी इमरान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके घर के पास एक खाली पड़े प्लाट पर अवैध निर्माण शुरू किया जा रहा है। उसने मामले की शिकायत पुलिस व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्लाट पर नींव डाल दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम व पुलिस को अवैध निर्माण को रोकने के आदेश दिए। इस मामले में इस वर्ष 19 मई को नींव डालने की बात अदालत को बताई गई। 1 जून को पहली मंजिल बनाए जाने, 20 जुलाई को दूसरी, 25 जुलाई को तीसरी और 13 अगस्त को चौथी मंजिल बनाए जाने की सूचना अदालत को दी गई। अदालत ने पूर्व में ही इस अवैध निर्माण को रोकने के आदेश दिए थे। मामले में नगर निगम का कहना था कि उन्होंने 25 जुलाई को ही काम रोकने का नोटिस जारी कर दिया था। मगर, उन्हें पुलिस की ओर से मदद नहीं दी गई। पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने डीसीपी को तलब किया था।

# 'केजरी पर हमले की योजना बना रही भाजपा'

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :** आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी का एक नेता पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला है। 24 अगस्त, रविवार को बाहरी दिल्ली के किराड़ी में होने वाली केजरीवाल की जनसभा में उन पर हमला करने की योजना है।

आप नेताओं ने इस आरोप का आधार एक न्यूज चैनल के स्टिंग को बनाया है। इस स्टिंग में किराड़ी से भाजपा विधायक अनिल झा के करीबी लोकेश नाम के व्यक्ति को कुबूल करते हुए दिखाया गया है कि वह किराड़ी में होने वाली रैली के दौरान केजरीवाल पर हमले की योजना बना रहा है।

पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद पर कई बार हमले हुए थे। उन्होंने स्टिंग का हवाला देते हुए केजरीवाल पर हुए सभी हमलों को सुनियोजित साजिश करार दिया। आशुतोष ने कहा कि चूंकि स्टिंग में लोकेश नाम का व्यक्ति किराड़ी से भाजपा विधायक अनिल झा से संबध होने की बात कह रहा है, उससे लगता है कि यह सब भाजपा की साजिश है।

आप सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। हम ऐसी ओछी राजनीति नहीं करते। आरोप निराधार हैं। -अनिल झा, भाजपा विधायक, किराड़ी

### आरडब्ल्यूए को जोड़ने का केजरी ने दिया टास्क

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :** राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) अपने स्तर से तैयारी शुरू कर चुकी है। इस कड़ी में पिछले दिनों शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपने सभी विधायक व टिकट के दावेदारों के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक की। केजरीवाल ने सभी नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 5 से 7 आरडब्ल्यूए को पार्टी से जोड़ने का टास्क दिया है। केजरीवाल के नेतृत्व में हुई बैठक में आरडब्ल्यूए सदस्यों को जोड़ने के लिए पार्टी ने जल्द ही एक मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। सूत्रों की मानें तो पार्टी ने हर विधानसभा में अधिक से अधिक आरडब्ल्यूए को शामिल कर उनसे जुड़े सदस्यों के जरिए अधिक से अधिक मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य दिया है। गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया था, उसके बेहतर नतीजे आए थे।

# सरकार के काम से नाराज है भाजपा

**राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :** केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से शनिवार को हुई प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में गृहमंत्री से शिकायत की है। जिसमें कहा कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी व बाबू जनता को परेशान कर रहे हैं। उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गृहमंत्री ने उपराज्यपाल की बैठक बुलाए जाने की बात कही है।

ज्ञात हो कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से शनिवार को मिला। प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री को जनसेवाओं से जुड़े विभागों में काम करने वाले अधिकारियों की हठधर्मिता से अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि फूड एंड सिविल सप्लाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे विभागों में आम जनता को अधिकारियों की उपेक्षा सहन करनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग में अनियमितताएं हैं। वहीं जनता को राशनकार्ड एवं विभिन्न प्रकार की पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। अस्पतालों में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह भी बताया गया कि शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचरों का मसला उलझाए रखने के कारण नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के बाद भी स्कूलों में पढ़ाई सुचारू नहीं हो पा रही है। इस सबका मूल कारण है विभागों के मुख्य अधिकारियों द्वारा अपनाया जा रहा टालमटोल व अनिर्णय का रवैया है। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के प्रदेश प्रभारी प्रभात झा, राष्ट्रीय मंत्री सरदार आरपी सिंह, संगठन महामंत्री विजय शर्मा, विधायक जगदीश मुखी, साहिब सिंह चौहान, मोहन सिंह बिष्ट, सुभाष सचदेवा, कुलवंत राणा समेत कई नेता शामिल थे।

सभी नेताओं ने गृह मंत्री को यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। समस्याओं या जुर्म को रोकने की बजाय निजी भवन निर्माण के कार्यों के निरीक्षण में ज्यादा रूचि लेते हैं। उपाध्याय का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से इन सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।

- केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने की मुलाकात

**पाठकों के लिए**
अपरिहार्य कारणों से आज के अंक में वैवाहिक विज्ञापन (शहनाई) प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। कृपया कल के अंक में देखें।
महाप्रबंधक

**डायलिसिस से बचा जा सकता है**
अब गुर्दे फेल मरीजों का इलाज संभव है।
हम 35 वर्षों से गुर्दों का इलाज कर रहें हैं। Estd : 1974
KUNDAN KIDNEY CARE CENTRE
for more details visit or call :
H.O. : Jalandhar, B.O. : Chandigarh
+91 96 5353 7575
+91 96 5353 9595
Visit www.kundankidneycare.com
Email : info@kundankidneycare.com


### झुग्गियों में जनाधार बढ़ाना चाहती है पार्टी

# केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाएगी भाजपा

- अनधिकृत कालोनियों के मतदाताओं पर है नजर
- जन-धन योजना को लेकर प्रदेश भाजपा गंभीर

**संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली**

दिल्ली में सरकार बनाकर सूबे की जनता के बीच अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश को सफल न होता देख भाजपा ने अब केंद्र सरकार की योजनाओं का सियासी लाभ उठाने की दिशा में कवायद तेज कर दी है। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा दिल्ली व पड़ोसी शहरों के बीच यातायात सुगम बनाने जैसी केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने की पहल कर चुकी पार्टी ने अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के बहाने गरीबों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की मुहिम शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना में गरीब परिवारों का बैंक अकाउंट खोला जाएगा। दिल्ली में इस योजना को सफल बनाने के लिए भाजपा सांसदों, विधायकों, पार्षदों व पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। वे लोगों के बीच जाकर इस योजना को प्रचारित करने के साथ ही लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाने में भी मदद करेंगे।

भाजपा नेताओं का मानना है कि इस योजना से झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों का वहां रहने वाले लोगों के साथ जुड़ाव भी बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं को भी पार्टी की नीतियां लेकर इनके बीच जाने में आसानी होगी। इस योजना से मिलने वाले सियासी लाभ को ध्यान में रखकर प्रदेश भाजपा इसे लेकर काफी गंभीर है। प्रदेश संगठन महामंत्री को इसकी प्रगति की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे यह पता चल सके कि जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा रहे हैं या नहीं।

इसके लिए पार्टी ने विधायक व पार्षदों को झुग्गियों में शौचालय का निर्माण व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्रचारित करने का निर्देश भी दिया है।उल्लेखनीय है कि झुग्गी-झोपड़ी व अनधिकृत कॉलोनियों में अभी भी भाजपा की पकड़ कमजोर है। जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता के पीछे यहां रहने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसी ताकत के भरोसे अरविंद केजरीवाल भाजपा पर विधानसभा चुनाव कराने के लिए दबाव बना रहे है। इसलिए भाजपा इन इलाकों में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भविष्य में इस तरह के कुछ और कदम उठाए जाएंगे, जिससे वह आप के वोट बैंक में सेंध लगाकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सके।


www.renault.co.in

बड़ी, खूबसूरत, दमदार रेनो डस्टर से बढ़िया आज़ादी की अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। 4 साल की मुफ़्त रोड साइड सहायता सेवा के साथ तो यह और भी बेहतर है। तो आएं, और इस आज़ादी के मौके पर रेनो डस्टर घर लेकर जाएं। इसके अलावा, इस अगस्त कोई भी रेनो खरीदें और थाइलैंड की निश्चित यात्रा जीतें।

टेस्ट ड्राइव के लिए 53030 पर 'Duster' SMS करें या लॉग ऑन करें: www.renault.co.in पर

DRIVE THE CHANGE

RENAULT

Follow us on /Renaultindia

*Benefit of up to ₹45,000 applicable under Exchange offer on 85 PS RxE, 85 PS RxL & 85 PS RxE Adventure Edition only. 'Benefits of up to ₹30,000 is applicable under Non-exchange for mentioned variants. **The above EMI is for first year on a loan amount of ₹5,70,000. EMI is calculated based on Step up & Bullet for a tenure of 5 years. EMI will vary with loan amount & tenure. Loan approval at the sole discretion of financier. Contact our dealers for more details. Accessories shown may not be part of the standard fitment. ^^Warranty coverage 2+2 years / 80,000 km. from the date of invoice (whichever is earlier). Assured trip to Thailand offer is valid on all variants. For detailed terms & conditions, please visit www.renault.co.in

**SHOWROOMS: NCR: DELHI SOUTH:** RENAULT Adhchini Mob: +91 70421 96747. RENAULT Delhi South Mob: +91 92129 88000. **DELHI WEST:** RENAULT Delhi West Tel: +91 11 4999 4666, Mob: +91 88606 06068. **DELHI NORTH:** RENAULT Delhi North Tel: +91 11 4999 6644, Mob: +91 88606 06069. **DELHI EAST:** RENAULT Delhi East Tel: +91 11 4302 2555, Mob: +91 83739 08032. **FARIDABAD:** RENAULT Faridabad Tel: +91 129 4245 000, Mob: + 91 88260 79999. **GURGAON:** Sohna Road Mob: +91 88006 01918, +91 85275 90090. Old Palam-Gurgaon Road Mob: +91 85275 90081, +91 88006 01899. RENAULT Gurgaon Mob: +91 92129 88000. **GHAZIABAD:** RENAULT Ghaziabad Mob: +91 85880 22000. **NOIDA:** RENAULT Noida Tel: +91 120 429 9901, Mob: +91 83739 10914. **SONEPAT:** RENAULT Sonepat Mob: +91 8929140140, +91 86070 75656.

L&K | SAATCHI & SAATCHI